

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (HQs.):
TIS HAZARI COURTS, DELHI

No. 57943 - 52143 /Admn.I/Estt./2025

Dated

15 OCT 2025

❖ Copy of the notification dated 22.09.2025 of the Hon'ble High Court of Delhi regarding the amendment to the Delhi District Courts Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2012 which are called the "Delhi District Courts Establishment (Appointment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2025" is forwarded herewith for information and further necessary action at your end.

1. All the Ld. Principal District & Sessions Judges, Delhi/New Delhi with the request to circulate the same in their respective districts for information and necessary action.
2. The Ld. Principal Judge, Family Courts (HQs.), Dwarka Courts, New Delhi.
3. All the Ld. Judicial Officers posted in Central District, Tis Hazari Courts, Delhi.
4. The Chairman, Website Committee, Tis Hazari Courts, Delhi with the request to upload the same on the Website of Delhi District Courts as per rules.
5. All the branches of Central District, Tis Hazari Courts, Delhi.
6. Dealing Official for uploading the same on Centralized Website through LAYERS as per rules.
7. PS to the undersigned.

[Signature]
15/10/2025

(VIRENDER KUMAR BANSAL)

Principal District & Sessions Judge (HQs.): Delhi

1. Ld. OJC Admn. Bt
for information and
necessary compliance.

2. ✓ Ld. OJC Comp Bt
with the request to upload
the same on the website of
Rohini Courts.

PDD/SJ/NW
16/10/2025

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266649
SG-DL-E-06102025-2666492464
10-9 OCT 2025असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/ आश्विन 1, 1947

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 251

No. 41]

DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

[N. C. T. D. No. 251

भाग II—I

PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सं. 68/नियम/दि.उ.न्या.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एक 27/40/50-गनजीएम, दिनांक 28 अक्टूबर, 1953 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित एवं माननीय उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सहमति से दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करता है:

एन सी टी, एन सी टी / Selection Committee
एन सी टी / Establishment

6310 DG-2025

(1)

Estb.

Br. Ineh
13/11/25

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266649
SG-DL-E-06102025-266649

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/ आश्विन 1, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 251
No. 41]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947	[N. C. T. D. No. 251

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सं. 68/नियम/दि.उ.न्या.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ27/40/50-एनजीएस, दिनांक 28 अक्टूबर, 1953 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित एवं माननीय उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सहमति से दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करता है:

संशोधन

यह नियम "दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2025" कहलाएंगे।

क्र. सं.	नियम	संशोधन
1.	नियम 2(1)(ख) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:	समूह ए तथा अन्य समूहों में अन्य सभी पदों से तात्पर्य उस जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से है जहाँ इन नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है
2.	नियम 2(5) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:	"जिला" से तात्पर्य उस जिला से है जिसे समय समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किया जाएगा
3.	नियम 2(6) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:	"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश" से तात्पर्य संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश है;
4.	नियम 2(13) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:	"अनुशंसा समिति" से तात्पर्य वह समिति जो प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं उससे ऊपर के पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों को उच्च न्यायालय में अनुशंसा करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गयी है एवं वह निम्नलिखित से मिलकर बनी होगी : (i) एक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अध्यक्ष के रूप में); एवं (ii) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के दो सदस्य जिनकी कम से कम दस वर्षों की सेवा हो। जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक आधार पर अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए नामित किया जाएगा।
5.	नियम 2(14) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:	"एकीकृत भर्ती समिति" सभी पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए किसी भी जिले में सीधी भर्ती की जानी है, उच्च न्यायालय निम्नलिखित को मिलाकर एक स्थायी एकीकृत भर्ती समिति का गठन करेगा : (i) एक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अध्यक्ष के रूप में); एवं (ii) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के दो सदस्य जिनकी कम से कम दस वर्षों की सेवा हो। जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक आधार पर अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए नामित किया जाएगा। स्पष्टीकरण : समूह -सी के पदों में 10 अथवा उससे अधिक रिक्तियों में भर्ती करने हेतु गठित भर्ती समिति के लिए यह आजापक होगा कि वह अनु. जा./अनु.जन. के समुदाय का एक सदस्य रखें।

14.	वरिष्ठ निजी सहायक [पदोन्नति/चयनित पद] (गैर-राजपत्रित) वेतनमान-II- 9300- 34800 + 4600/-	क) 50% रिक्त पद पदोन्नति द्वारा निजी सहायक से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर, कंप्यूटर/टाइपराइटर पर लिप्यंतरित किए जाने वाले शॉर्टहैंड डिक्टेशन के आधार पर। "बशर्ते निजी सहायक, जिन्होंने आठ (8) वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वरिष्ठ निजी सहायक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। ऐसे पदोन्नत कर्मचारी उस वर्ष की वरिष्ठता सूची के अंत में एक साथ (en bloc) दर्शाए जायेंगे जिस वर्ष वे वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर पदोन्नत हुए हैं। ऐसे पदोन्नत कर्मचारी निजी सहायक के कैडर में उनके बीच पारस्परिक वरिष्ठता को बनाए रखेंगे। वे वरिष्ठ निजी सहायक के कैडर में उक्त वर्ष या पूर्व वर्षों में पदोन्नत हुए कर्मचारियों से कनिष्ठ होंगे। यदि उक्त श्रेणी में किसी कनिष्ठ ने आठ (8) वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो तो उनसे वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते यह कमी छह माह से कम हो। इस परन्तुक के अंतर्गत की गई पदोन्नति व्यवस्थित की जायेगी तथा 50 % पदोन्नति कोटे से होगी। ख) 50% रिक्त पद सीधे भर्ती द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर, जिसमें अंग्रेजी भाषा (निबंध, व्याकरण और अनुवाद) का एक पेपर शामिल होगा, इसके बाद शॉर्टहैंड डिक्टेशन होगी जिसे कंप्यूटर/टाइपराइटर पर लिप्यंतरित करना होगा। इनमें से चुने गए अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। ब) सीधी भर्ती हेतु: शॉर्टहैंड में न्यूनतम 110 शब्द प्रति मिनट तथा टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ज्ञातक।	क) स्थापना के सदस्यों हेतु: निजी सहायक के रूप में 3 वर्ष की सेवा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
-----	--	---	---

IV. "नियम 2012" की अनुसूची ख के वर्तमान क्रम संख्या 21 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्र. सं.	पद का नाम	चयन की पद्धति	अर्हता आदि	नियुक्ति प्राधिकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	चालक/स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) वेतनमान-II- 9300-34800+4200/-	चालक/स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) की श्रेणी से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की स्थापना में चालक/स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) के कैडर में तीन वर्ष की नियमित सेवा।	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

टिप्पणी: यह संशोधन इनके राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महातिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2025

No. 68/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F27/40/50-NGS dated the 28th October, 1953 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Central Government and the concurrence of Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in Delhi District Courts Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2012:

AMENDMENTS

These rules may be called "Delhi District Courts Establishment (Appointment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2025".

S.No.	Rules	Amendments
1.	For rule 2(1)(B), the following rule shall be substituted:	All other posts in Group A and in other Groups means the Principal District and Sessions Judge of the District to which staff is allocated under these Rules.
2.	For rule 2(5), the following rule shall be substituted:	"District" means the District notified by the Government of NCT from time to time.
3.	For rule 2(6), the following rule shall be substituted:	"Principal District & Sessions Judge" means the Principal District & Sessions Judge of the concerned District
4.	For rule 2(13), the following rule shall be substituted:	"Recommendation Committee" constituted by the High Court for the purpose of making recommendations to the High Court of the names of suitable candidates for the post of Administrative Officer(Judicial) and above and shall comprise of:- - One Principal District & Sessions Judge (as Chairman); and - Two members of Delhi Higher Judicial Service having at least ten years of service to be nominated by the High Court on an yearly basis or for a specified period.
5.	For rule 2(14), the following rule shall be substituted:	"Unified Recruitment Committee"— In respect of all posts to which direct recruitment is to be made in any District, the High Court shall constitute a permanent Unified Recruitment Committee comprising:- - One Principal District & Sessions Judge (as Chairman); and - Two members of Delhi Higher Judicial Service having atleast ten years of service to be nominated by the High Court on an yearly basis or for a specified period. Explanation: It shall be mandatory for a Recruitment Committee constituted for making recruitments for 10 or more vacancies in Group-C posts to have one member of SC/ST community.
6.	For rule 2(15), the following rule shall be substituted:	"Selection Committee" in respect of:- - Post of Administrative Officer (Judicial) and above means a Committee comprising of such number of Hon'ble Judges of High Court as the Hon'ble Chief Justice may deem appropriate. - All other posts in Group A and other Groups means one or more Committee or Committees constituted by the High Court comprising of: - One Principal District & Sessions Judge; - One member of Delhi Higher Judicial Service having at least ten years of service; and - One Chief Metropolitan Magistrate or Senior Civil Judge or Additional Chief Metropolitan Magistrate or Administrative Civil Judge to be nominated by the High Court on an yearly basis or for a specified period. Explanation: It shall be mandatory for a Selection Committee constituted qua Group-C post to have one member of SC/ST community.
7.	Amendment in rule 3	Sub Rule 2A shall be inserted after Sub Rule 2 in the following manner: 2A. The High Court, after coming into force of the "Delhi District Courts Establishment (Appointment & Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2025 and thereafter from time to time, shall, out of the posts specified in column (2) of Schedule A, allocate such number of posts to each District, as it considers appropriate keeping in mind the number of judicial officers, judicial and administrative work and such other criteria as the High Court may consider relevant. Sub Rule 5 shall be inserted in Rule 3 in the following manner: The High Court shall, after coming into force of the "Delhi District Courts Establishment (Appointment & Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2025, on the basis of such criteria as formulated by it, allocate district wise, the persons holding any of the posts specified in Schedule A.

		Explanation:- No officer/official shall be allowed to change the allocated district except under exceptional circumstances for which approval of High Court shall be necessary.
8.	For rule 5, the following rule shall be substituted:	Procedure to appoint Principal Private Secretary:- It shall be the sole discretion of the Principal District & Sessions Judge concerned to appoint his/her Principal Private Secretary from amongst the pool of Administrative Officers (Judicial) working in the district concerned and such person shall continue to hold the said post for such period as may be desired by the concerned Principal District & Sessions Judge.
9.	Amendment in rule 7	The last para of rule 7 (after the point no. f) shall be substituted as below:- on the last date fixed for the receipt of applications or on such other date as may be specified by the High Court in the notification inviting applications.
10.	For rule 9, the following rule shall be substituted:	District Courts Recruitment Cell:- High Court shall constitute 'District Courts Recruitment Cell' which shall function as per the administrative instructions issued by the High Court from time to time
11.	For rule 10, the following rule shall be substituted:	Direct recruitment:- Direct recruitment to all posts shall be made through the Unified Recruitment Committee in accordance with these Rules and the administrative instructions issued by the High Court from time to time.
12.	Amendment in rule 11	The word "Recruitment Committee" changed as " Unified Recruitment Committee".
13.	Amendment in rule 12	Recruitment Committee changed as Unified Recruitment Committee. The words "in consultation with the District Judge and" shall stand deleted. The words "The District Judge shall, in consultation with the Chairman(s) of the Committee(s) lay down appropriate criteria for interviewing to assess the suitability of the candidates for appointment to the post applied for by them including intellectual and social traits of personality so as to maintain uniformity of standards in the process of interviewing candidates" shall stand deleted.
14.	For rule 13, the following rule shall be substituted:	The words "in such format as may be desired by the District Judge" shall stand deleted. List of selected candidates:- 1. After preparation of the list of selected candidates, the Unified Recruitment Committee shall place it before the High Court for final approval. After approval, the Registrar (District Courts Recruitment) shall allocate the selected candidates to various districts in terms of the preferences expressed by them. In case the number of candidates opting for a particular district is more than the number of vacancies of that post in the particular district, the candidate securing higher position in the merit list shall be allocated the District of his choice. 2. The Unified Recruitment Committee shall also prepare a panel of candidates in the order of merit containing the names of candidates not included in the select list prepared under sub-rule (1) in which the number of candidates to be included shall, as far as possible, be ten percent of the number of vacancies notified. 3. The list so prepared under Sub-Rules (1) and (2) shall be published in such manner as the High Court may direct.
15.	For rule 14, the following rule shall be substituted:	Appointment of candidates:- (1) Subject to Rule 16, candidates whose names are included in the select list prepared under sub-rule (1) and published under sub-rule (3) of rule 13, may be appointed by the Appointing Authority against the vacancies in the particular cadre of the particular District in the order in which the names are found in the select list after satisfying itself, after such enquiry as may be considered necessary that each such candidate is suitable in all respects for appointment to a post in the cadre. Candidates, whose names are included in the list prepared under sub-rule (2) and published under sub-rule (3) of rule 13, may be similarly appointed against vacant posts still available after the candidates whose names are included in the list prepared under Sub-Rule (1) of Rule 13 have been appointed. (2) The inclusion of the name of a candidate, in any of the two lists published under Rule 13, shall not confer on him any right of appointment.
16.	For rule 19, the following rule shall be substituted:	Recruitment by Promotion:- (1) The Principal District and Sessions Judge concerned shall make an assessment in the month of January, every year, of number of promotion vacancies existing and likely to occur during the year in different category of posts in the particular District. (2) The Principal District and Sessions Judge shall notify the vacancies for the posts of Administrative Officer (Judicial) and above in the particular District and shall forward the list of all eligible candidates falling in the zone of consideration for appointment to those posts to the Recommendation Committee. The Recommendation Committee, in accordance with the criteria laid down by the High Court shall prepare a list of suitable candidates for their appointment on promotion to the quota of 50% of the posts of Administrative Officer (Judicial) by way of promotion on the basis of suitability-cum-merit and for remaining 50% of posts shall conduct a departmental exam followed by an interview. The Committee shall thereafter forward the list of persons so selected along with the list of the persons not found suitable stating the reasons for the same to the High Court. The list so received shall then be placed before the Selection Committee constituted by the Chief Justice of

		the High Court under Rule 2 (15)(a) and the Selection Committee may either accept or reject the recommendations of the Committee or suitably modify the list as it may deem fit. The final list shall then be placed before the Chief Justice for his consideration and who shall thereafter forward it to the Full Court for approval. (3) Deleted. (4) The Principal District and Sessions Judge shall also notify the vacancies for all other posts in Group-A and other Groups in the particular district and shall forward the list of all eligible candidates falling in the zone of consideration for appointment to those posts to the Selection Committee. The Committee, in accordance with the criteria laid down by the High Court shall prepare a consolidated list of suitable candidates for all districts. However, for the post of Senior Judicial Assistant, the Selection Committee, shall prepare a list of suitable candidates for their appointment on promotion to the quota of 50% by way of promotion on the basis of suitability-cum-merit and for remaining 50% of posts shall conduct a departmental examination followed by an interview. The Committee shall thereafter forward the list of persons so selected along with the list of the persons not found suitable stating the reasons for the same to the High Court for final approval through Principal District and Sessions Judge of the District concerned. (5) The High Court shall lay down the criteria to determine the merits of a candidate.
17.	For rule 20, the following rule shall be substituted:	Appointment:- On approval of the list of selected candidates of promotion under Rule-19, the Registrar (District Courts Recruitment Cell) shall allocate the candidates to the districts, keeping in mind the allocated vacant post in such district and send such list to the Principal District and Sessions Judge concerned who then shall make appointment of the candidates so selected after making enquiry as may be considered necessary or pass such orders as may be deemed appropriate.
18.	For rule 27, the following rule shall be substituted:	Disciplinary Authorities:- (1) The High Court may impose any of the penalties specified in Rule 26 on any Member of the Service. (2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) the Principal District and Sessions Judge may impose any of the penalties specified in Rule 26 on any Member of the Service for which the Appointing Authority is the Principal District & Sessions Judge. (3) The Principal District and Sessions Judge shall also be empowered to impose any of the penalties enumerated in clauses (i) to (iv) of Rule 26 on any Member of the Service of which High Court is the Appointing Authority. Explanation:- The Principal District & Sessions Judge under whose jurisdiction, the alleged misconduct or misbehavior is committed by any Member of the service, shall be the Disciplinary Authority even where such member is transferred to other district.
19.	For rule 28, the following rule shall be substituted:	Authority to institute proceedings:- The High Court, by general or special order, may— 1. Institute disciplinary proceedings against any Member of the Service 2. Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) the High Court may direct the Principal District and Sessions Judge of the District concerned to institute disciplinary proceedings against any Member of the Service on whom the Principal District and Sessions Judge of the District concerned is competent to impose under these rules any of the penalties specified in Rule 26. 3. The Principal District and Sessions Judge of the District concerned competent under these rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of Rule 26 may institute disciplinary proceedings against any Member of the Service of the concerned District for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Rule 26 notwithstanding that the Principal District and Sessions Judge of the District concerned is not competent under these rules to impose any of the later penalties. EXPLANATION—On the conclusion of the inquiry or receipt of the inquiry report if the Disciplinary Authority comes to the conclusion that a minor penalty will meet requirement of the case it will be well within his competence to impose the minor penalty without seeking the approval of the High Court which is competent to impose a major penalty on the member of the Service concerned.
20.	Amendment in rule 33	The word "President" shall be replaced with "High Court".
21.	Amendment in rule 34	The word "President" in Sub-Rule (iii) shall be replaced with words "High Court".
22.	For rule 39, the following rule shall be substituted:	Retirement in public interest:- Notwithstanding anything contained in these rules or any other law, the High Court or the Principal District & Sessions Judge may, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any member of the Service who has put in not less than twenty five years of service or has attained the age of 50 years, by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice.
23.	For rule 44, the following rule shall	Power to relax:-

	be substituted:	Where the Principal District & Sessions Judge, is satisfied that the operation of any rule causes undue hardship in any particular case, he or she may send a recommendation to the High Court for dispensing with or relaxing the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as he or she may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner provided that the case is not dealt with in a manner less favourable to the officer or officials concerned than in accordance with rules, and the High Court shall take a decision on such recommendation which shall be final.
24.	Amendment in Schedule-B	Column 5 – wherever the word “District Judge” appears the same shall be replaced with the words “Principal District and Sessions Judge” Column 4 of Sl. No. 4, 10 and 16 “District Judge” shall be replaced with “High Court” in the matter of relaxation of qualification and experience.
25.		Wherever the words “District Judge” are appearing in the Rules, the same shall be replaced with the words “Principal District & Sessions Judge”

II. The following shall be substituted for the existing Sr.No.3 of Group-A of Schedule-B:-

Srl. No.	Name of the Post	Method of Recruitment	Qualification etc.	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Administrative Officer (Judicial) [Promotion/ Selection post] (Gazetted) PB-III-15600-39100+6600/-	a) 50% of the sanctioned strength by promotion on the basis of seniority-cum-merit from Senior Judicial Assistants, Senior Personal Assistants and Civil Nazirs / District Nazirs shall be filled according to the percentage of cadre strength of above three category i.e 60%, 30% and 10% respectively. b) 50% of the sanctioned strength by selection on the basis of written test and interview from Senior Judicial Assistants, Senior Personal Assistants and Civil Nazirs / District Nazirs, Judicial Assistant, Personal Assistant or combined service in any of these posts. c) In case requisite number of candidates do not qualify for selection on merit in terms of provisions of clause (b) above, by direct recruitment on the basis of written test and interview.	a) Graduate with 5 years service (Law Graduate to be preferred) in any of the posts of Senior Judicial Assistants, Senior Personal Assistants and Civil Nazirs/District Nazirs. b) Graduate with 5 years service (Law Graduate to be preferred) in any of the posts of Senior Judicial Assistants, Senior Personal Assistants and Civil Nazirs/District Nazirs. OR Graduate with 7 years regular service (Law Graduate to be preferred) in the post of Judicial Assistant/Personal Assistant or combined service in any of these posts. c) For Direct Recruits : Law Graduate with 5 years service in the grade pay of Rs. 4600/-.	High Court

III. The following shall be substituted for the existing Sr.No.14 of Schedule-B:-

Srl. No.	Name of the Post	Method of Recruitment	Qualification etc.	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Senior Personal Assistant (Promotion/ Selection Post) (Non-Gazetted) PB-II-9300-34800+4600/-	a) 50% of the vacant posts by promotion from Personal Assistants on the basis of seniority-cum-suitability on the basis of shorthand dictation to be transcribed on Computer /Typewriter. “Provided, Personal Assistants, who have completed eight (8) years of regular service would be promoted as Senior Personal Assistant. Such promotees would be en bloc shown at the bottom of the seniority list in the year in which they were promoted as Sr. Personal Assistants. Such promotees would maintain inter se seniority between them in the cadre of Personal Assistant. They would be junior to those promoted in the cadre of Senior Personal Assistant in the said year or earlier years. In case a junior in the said category has completed eight (8) years of regular service, his senior would also be considered, provided the shortfall is less than six (6) months. Promotions made under this proviso would be adjusted and from the 50% promotion quota.” b) 50% of the vacant posts by direct recruitment on the basis of written examination comprising of one paper in English language (Essay, Grammar and Translation) followed by a Shorthand dictation to be transcribed on Computer/Typewriter. The short listed candidates would also undergo a viva voce test.	a) For members of the Establishment: 3 years service as Personal Assistant. b) For direct recruits: Graduate with speed of not less than 110 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting.	Principal District and Sessions Judge

IV. The following shall be substituted for the existing Sr.No.21 of Schedule-B of “Rules 2012”:-

9

Srl. No.	Name of the Post	Method of Recruitment	Qualification etc.	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	Driver/Staff Car Driver (Special Grade) PB-II-9300-34800+4200/-	By promotion on the basis of seniority-cum-merit from the category of Driver/Staff car driver (Grade-I)	Three years Regular service in the cadre of Driver/Staff Car Driver (Grade-I) in the establishment of the District & Sessions Judge, Delhi	Principal District and Sessions Judge
Srl. No.	Name of the Post	Method of Recruitment	Qualification etc.	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	Driver Staff Car Driver (Special Grade) PB-II-9300-34800+4200/-	By promotion on the basis of seniority-cum-merit from the category of Driver/Staff car driver (Grade-I)	Three years Regular service in the cadre of Driver Staff Car Driver (Grade-I) in the establishment of the District & Sessions Judge, Delhi	Principal District and Sessions Judge

NOTE: These Amendment Shall Come Into Force From The Date Of Their Publication In The Gazette.

By Order of this Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General